श्री संजय निरूपम: अपने कुछ नई ट्रेनें शुरू करने की बात की थी। लेकिन नई ट्रेने शुरू करने के बजाय पुरानी ट्रेनों में कुछ डिब्बे और जोड़ दिए गए हैं।

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': माननीय रेल मंत्री जी ने बताया कि किन-किन लाईनों पर विद्युतिकरण करने को प्राथमिकता दी जा रही है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उसकी राजधानी लखनऊ है और जिस राज्य से माननीय मंत्री जी आते हैं उसकी राजधानी पटना है। इसकी दिल्ली से सीधा विद्युतिकरण करने की कोई योजना विचाराधीन है या नहीं, यह जानकारी देने का कष्ट करें।

श्री राम विलास पासवान: मैं यह सूचना माननीय सदस्य को लिख कर बतला दूंगा।

Newsitem Captioned "Airlines vexed by Pollution Tax Move"

*225. SHRI KRISHNA KUAMR BIRLA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Goverment's attention has been drawn towards the newsitem captioned "Airlines vexed by pollution tax move", as reported in the "Economic Times", dated the 3rd September, 1996;

(b) if so, whether pollution in the atmosphere is increasing;

(c) whether planes of various airlines are the major pollution creators in the atmosphere; and

(d) if so, the steps Government propsoe to take to check pollution caused by planes in the atmosphere?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। वायुयान वातावरण प्रदूषण के प्रमुख स्रोत नहीं हैं। वातावरण प्रदूषण के अन्य कई स्रोत हैं जिनमें उद्योग, ताप विद्युत संयंत्र, वाहन आदि शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

SHRI KRISHNA KUAMR BIRLA: Sir, let the Minister read out the answer.

केप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: सर,

(क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं, वायुयान वातावरण प्रदूषण के प्रमुख स्रोत नहीं हैं। वातावरण प्रदूषण के अन्य कई स्रोत हैं जिनमें उद्योग, ताप विद्युत संयंत्र, वाहन आदि शामिल हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Sir, I don't have any supplementary.

MR. CHAIRMAN: No supplementary!

SHRI KRISHNA KUAMR BIRLA: Sir, I am satisfied with the answer.

*226. [*The questioners (Shri V. Rajeshwar Rao and Dr. Shrikant Ramchandra Jichar) were absent for answer vide col. 30 infra.*]

Development of Animal Husbandry and Dairying in the North-East

*227. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state the details of the steps/projects undertaken by Government for the development of dairies and animal husbandry in Assam and other States of the North-East Region during the preceding three years and the current year?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा० रघुवंश प्रसाद सिंह): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई गई परियोजनाओं/योजनाओं की सूची संलग्न विवरण पर दी गई है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान पशुपालन एवं डेयरी के विकास के लिए क्रियान्वित परियोजनाओं/योजनाओं की सूची

पशुपालन

केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं

1. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार।
2. आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।
3. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।
4. पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।
5. व्यावसायिक कार्यकुशलता विकास।

6. बूचड़खानों/पशुशव उपयोग केन्द्र तथा प्राथमिक निस्त्वचन एककों के सुधार/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता।

7. प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन के अनुमान के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण।

8. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।

9. राष्ट्रीय मेढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम तथा खरगोश विलय कार्यक्रम।

10. भारवाही पशु विलास।

11. एकीकृत सुअर विकास के लिए राज्यों को सहायता।

केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं

12. पशुपालन विकास कार्यक्रम।

13. विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम।

डेयरी विकास
केन्द्रीय क्षेत्र योजना

14. गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजनाएं।

SHRI PARAG CHALIHA: Sir, my question was in relation to animal husbandry and other works in the North-East in general and in Assam in particular. But the answers relate to the projects during the Eighth Plan without in any way specifying the years about which I put the question. Will the Minister be pleased to do justice to my question.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, the question relates to North-East and Assam.

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, असम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुल सात राज्यों के संबंध में डेयरी और पशुपालन विभाग से संबंधित प्रश्न माननीय सदस्य का था, उस से संबंधित केन्द्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं में जितनी भी राशि दी गई है, उससे संबंधित विवरण उत्तर में दिया गया है। अब माननीय सदस्य अलग-अलग क्या जानना चाहते हैं? वे जो जानना चाहेंगे, मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

SHRI PARAG CHALIHA: Sir, my question was very specific. Will the Minister be pleased to state the details of the projects undertaken by the Government for the development of dairying and animal husbandry in Assam and in other States of the North-Eastern Region during the preceding three years and in the current year? The answer was just a list of all the projects undertaken during the Eighth Plan. My specific question is not answered at all. Will the Minister satisfy me in respect of my question?

MR. CHAIRMAN: The question specifically relates to the North-East and Assam. What are the projects?

SHRI PARAG CHALIHA: It has a political bearing also. Therefore, I want the details of the projects undertaken during the last three years as well as the current year.

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह: आठवीं पंचवर्षीय योजना में हर वर्ष कितना खर्च किया गया है, इसका विवरण दे दिया गया है।

श्री पराग चालिहा: कहां पर दिया गया है?

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह: सदन की मेज पर।

श्री पराग चालिहा: मेरे क्वैश्चन में क्यों नहीं दिया है?

My point is this. Why should I not get an answer which I wanted for a specific purpose?

MR. CHAIRMAN: The question specifically relates to the projects which have been carried out during the last three years in Assam and in other States of the North-East.

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में डेयरी और पशुपालन के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है? उससे संबंधित ब्यौरे में हमने जवाब में लिखा है कि हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम के विस्तार से संबंधित मदद दी गई है। आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता दी गई है। राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना आदि, इस तरह से 14 स्कीमें हैं और इन 14 स्कीमों के तहत विभिन्न राज्यों में कितनी राशि दी गई है, सभी का विवरण हमने इस ब्यौरे में दे दिया है।

MR. CHAIRMAN: The Minister is saying all the schemes are functioning in Assam and in the other States of the North-East.

SHRI PARAG CHALIHA: Chairman, Sir, I seek your protection. It is only a list of projects. My specific question has not been answered at all. That is my feeling.

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह: ये एमाउंट जानना चाहते हैं या क्या जानना चाहते हैं? पूछें, हम अभी सब बता देते हैं।

SHRI PARAG CHALIHA: Sir, I am putting the question again.

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, 14 योजनाएं हैं जिनमें से चार योजनाओं में सभी राज्यों ने पांच वर्षों में मदद ली है और सरकार ने मदद दी है। सात राज्यों में तीन परियोजनाओं में किसी ने दो वर्ष मदद ली है और किसी ने एक वर्ष। जब राज्य सरकार से प्रस्ताव आता है तो केन्द्र सरकार उनको मदद देती है लेकिन जब राज्य सरकार से प्रस्ताव नहीं आता तो केन्द्र सरकार से मदद नहीं दी जाती। यह सारा ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

DR. BIPLAB DASGUPTA: Mr. Chairman, Sir, animal husbandry, poultry and dairying are very important subjects. Unfortunately, they do not get the importance which they deserve. Agriculture prosperity in China largely depends on side-line activities mainly in poultry and dairying. In our country, particularly in places like the North-East Region and Darjeeling, it is relevant because irrigated agriculture cannot flourish there. In the absence of irrigated agriculture, animal husbandry and poultry are two occupations which can make an impact on the economy. What the Central Government can do is this. Money is one aspect of it. But, I think, two other things are more important than money. One thing is technology and the other thing is coordination. So far as various technologies which are used for animal husbandry are concerned, I think, there has been a tremendous change. For example, a lot of cattle in the North-East require upgradation. They are very low quality cattle. They require upgradation. Semen should be preserved properly through the new technology, liquid nitrogen technology. The semen which our farmers get is usually very old, outdated and unproductive. Its failure rate is usually very high. I would like to know from the hon. Minister what steps they are taking, not in terms of merely giving some money to some projects and getting satisfied, for technological upgradation of our cattle population in the North-East.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री जी ने नार्थ-ईस्ट के सातों राज्यों का भ्रमण किया था और उन्होंने निर्देश दिया है कि देश के बजट में जो उपबन्ध है उसमें से करीब 10 प्रतिशत उन सातों राज्यों में खर्च किया जाए। उन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन हो इसको सुनिश्चित करने के लिए सात में, क्वाटरली और मंथली उसके सेक्रेटरी विजिट करें। मतलब यह कि नार्थ-ईस्ट की समस्याओं के संबंध में सरकार इतनी जागरूक है कि उनके लिए खर्चे की जो योजनाएं प्रस्तावित हैं, उनका कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं, उसको परस्यू कर के लागू कराने का सरकार का निश्चय है। तकनीकी मामले से संबंधित जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है, उस संबंध में यह सही है कि एनीमल हसबेंड्री एंड डेयरी के मामले में दुनिया में बड़ा भारी अनुसंधान हुआ है। उन सभी अनुसंधानों के प्रति सरकार सजग है। इस देश के कोने-कोने में जो अनुसंधान हुआ है उस अनुसंधान से पशुपालकों को और राज्यों को लाभ पहुंचाया जाए, उसके संबंध में प्रजनन सीमेन बैंक हर एक राज्य में खोलने का निश्चय है और खोला गया है जिससे क्रास ब्रीडिंग के लिए, पशु प्रजनन के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं का प्रजनन हो और पशुपालकों को लाभ हो और राज्यों को भी लाभ हो, खासकर वहां के गरीब लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोग हैं, जिनकी आर्थिक हालत खराब है, जिनको पौष्टिक आहार की समस्या है, भोजन की समस्या है और बेरोजगारी की समस्या है, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो आधुनिक तकनीक का विकास हुआ है एनीमल हसबेंड्री एंड डेयरी के मामले में तो लोगों को वह टेक्नालाजी मिलेगी, वह आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया गया है, प्रजनन सीमेन बैंक का प्रबन्ध किया गया है, इमब्रीयो-टेक्नालाजी का विकास हुआ है। यहां की जो खराब नस्लें हैं, उन नस्लों की गायों में, भैंसों में इम्ब्रीयो-टेक्नालाजी से बढ़िया नस्ल के बच्चे पैदा कराये जा सके। ...(व्यवधान)...

श्री एस०एस० अहलुवालिया: सभापति महोदय, मंत्री जी ने बहुत लम्बा-चौड़ा ब्यौरा दिया है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें मालूम है कि पशुपालन विभाग में जो पैसा केन्द्र सरकार से जाता है एक बहुत बड़ा घोटाला आसाम में हुआ है, क्या इसके बारे में वह जानते हैं? वहां जो एनीमल हसबेंड्री घोटाला हुआ है उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है और कौन-कौन से मंत्री और कौन-कौन से मुख्य मंत्री उसमें इन्वाल्व्ड हैं? वह सदन को बताने की कृपा करेंगे।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय कार्यक्रम के हिसाब से पशुपालन के लिए जो नियम बनाया गया है उसी का नार्थ-ईस्ट पर लागू कर दिया गया है। नार्थ-ईस्ट में आप अभी भी मुर्गी पालन, भेड़ पालन और बकरी पालन के लिए मदद देते हैं। किन्तु इनको पता होना चाहिए कि आसाम में, पूरे नार्थ-ईस्ट में अंडे आन्ध्र प्रदेश से जाते हैं। वहां आपका पोल्ट्री डेवलपमेंट टोटली फेल है। वहां के लिए अंडों और मछली की रिकवायरमेंट आन्ध्र प्रदेश से पूरी होती है।

दूसरी बात यह है कि आपने वहां पर राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम लागू किया हुआ है। आपको यह पता होना चाहिए कि वहां पर सांडों की नहीं मिथुन की जरूरत है। पूरे नार्थ-ईस्ट में मिथुन की जरूरत है क्योंकि वहां के लोग मिथुन का मांस खाते हैं। उसके उत्पादन के लिए आपने कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं बनाया है। इन सात नार्थ-ईस्ट स्टेटों में अगर कोई सबसे ज्यादा भोज्य पदार्थ है तो वह है मिथुन का मांस। इसके लिए आपको मिथुन का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए आपने क्या कार्रवाई की है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, केन्द्र सरकार से किश्तों में राशि जाती है। और राज्य सरकार उसको खर्च कर लेती है। उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। उसकी छानबीन करके देख लेते हैं तब अगली राशि दी जाती है। इसलिए केन्द्र सरकार की राशि के घोटाले की सूचना केन्द्र सरकार को नहीं है। हम उस पर मुस्तैद और जागरूक हैं कि हमारा जो पैसा वहां जाये उसका समय पर सदुपयोग हो और खर्च होने के बाद ही अगली राशि उनको दी जाती है इसलिए घोटाला होने की बात ही नहीं है।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने अंडों और पोल्टरी डेवलपमेंट के बारे में पूछी है। यह सही है कि पूर्वांचल का क्षेत्र पोल्टरी के मामले में पीछे है और यह क्षेत्र अन्य मामलों में भी पीछे है। जिन राज्यों में पशुओं, पोल्टरी और एनीमल हसबेंडरी से संबंधित मामला है उस पर उनको तरजीह दी जाती है, उनको मदद दी जाती है। जहां लोग सूअर का मांस खाते हैं तो सूअर पालन के लिए उनको मदद दी जाती है और जहां मिथुन का मांस खाते हैं वहां मिथुन पालन के लिए मदद दी जाती है। इसके लिए राष्ट्रीय प्रोग्राम के अन्तर्गत जो आंचलिक विषय है उसके लिए आंचलिक योजना और जो राष्ट्रीय विषय है उसके लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जा रही है। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: मिथुन के लिए आंचलिक योजना कहां? ...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, दुनिया के मुल्कों की तुलना में अंडे की खपत अपने देश में प्रति व्यक्ति 30 अंडा प्रति वर्ष है जबकि दुनिया के देशों में प्रति वर्ष 80 अंडा है। लेकिन जो पिछड़े देश हैं उनकी खपत 60-70 अंडा है, जो विकसित देश हैं उनमें 300 अंडा प्रति वर्ष खपत है। इसलिए यहां अंडे का ज्यादा उत्पादन हो, इस मामले में दिन्दुस्तान का अंडा उत्पादन में पांचवां स्थान है। जो पिछड़े राज्य हैं, रीजनल इम्बेलेंस हैं उनके लिए विशेष योजना बनाकर उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Eloquent non-reply! Question No. 228.

Drives against anti-social elements at railway stations

*228. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether some drives against anti-social elements operating in railway stations at New Delhi, Delhi, Nizamuddin, Sabzi Mandi, Sarai Rohilla were undertaken by Special Task Force of Northern Railway in 1996;

(b) if so, the number of such elements arrested at each railway station in each quarter of 1996 besides pick-pockets; and

(c) whether such regular arrests made by periodical drives have made platforms of railways stations free from these anti-social elements?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1996 के दौरान दिल्ली क्षेत्र में समाज-विरोधी तत्वों के विरूद्ध अभियान चलाने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा कोई विशेष कार्य-बल गठित नहीं किया गया था। लेकिन वर्ष 1996 में दिल्ली रेलवे पुलिस द्वारा नई दिल्ली और दिल्ली मेन रेलवे स्टेशनों पर समाज-विरोधी तत्वों के विरूद्ध नियमित अभियान चलाए गए थे। उत्तर रेल ने भी अपनी ओर से बिना टिकट यात्रियों, अनधिकृत खोमचे वालों/वेंडरों तथा ऐसे ही अन्य तत्वों